

प्रेषक,

मनीषा पंवार,  
सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

कुलसचिव/वित्त नियंत्रक,  
श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय,  
बादशाहीथौल, टिहरी।

शिक्षा अनुभाग-6 (उच्च शिक्षा)

देहरादून

दिनांक: 07 जनवरी, 2014

विषय: वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 के आयोजनागत पक्ष (Plan) की मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या: एसडीएसयूवी/बजट/683/2013 दिनांक: 11.11.2013 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें विगत वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आयोजनागत पक्ष के मानक मद-20 सहायक अनुदान आदि में धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- उक्त संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के लिए वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु आयोजनागत पक्ष (Plan) में मानक मद-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता में प्राविधानित धनराशि ₹ 15000 हजार (अर्थात् ₹ एक करोड़ पचास लाख मात्र) के सापेक्ष प्रथम किस्त के रूप में कार्यालय व्यय के अवचनबद्ध मदों हेतु धनराशि ₹ 1,00,00,000/- (₹ एक करोड़ मात्र) वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों एवं निम्नांकित प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृत करते हुए आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय केवल अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किस्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार ही किया जाएगा, तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि के बिल जिला विद्यालय निरीक्षक (DSIO), टिहरी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे।
- विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जबकि गत वित्तीय वर्ष/वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार उपभोग कर लिया गया हो तथा कोई भी धनराशि अवशेष न हो। धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार ही किया जाएगा।
- व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर वित्त विभाग के निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में वेतन मदों के अतिरिक्त शेष मदों में मितव्ययता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल शीर्षक/मदवार बचत की कार्य योजना बना ली जाय। तदनुसार विशेषकर आयोजनेत्तर पक्ष में बचत करने का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित कर बचत किया जाना सुनिश्चित करें।
- नए पदों के सृजन/ढांचे, नई नीति निर्धारण अथवा वर्तमान नीति में संशोधन, करों/यूजर्स चार्जेज में संशोधन, निधियों का गठन, अनुदान राशि में संशोधन, नियमावलियाँ आदि सभी प्रकरण शासन को भेजे जाए ताकि वित्त विभाग आदि के परामर्श से अनुमोदन दिया जा सके।
- विभिन्न मदों में व्यय भार/देयता सृजित होने पर यथाशीघ्र धनराशि आहरित कर भुगतान की जाएगी एवं कोई भुगतान अनावश्यक लम्बित नहीं रखा जाएगा, क्योंकि उससे मासिक आधार पर व्यय की भ्रामक सूचना परिलक्षित होती है। इस संबंध में समस्त वित्तीय नियमों, विनियमों एवं वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में दिए गए दिशा-निर्देशों का भी पूर्णतः अनुपालन किया जाये।
- इस अनुदान का उपयोग शासन द्वारा अनुमोदित पदों तथा मदों पर ही किया जायेगा। किसी भी दशा में एक मद की धनराशि दूसरे मद में व्यय न की जाये अन्यथा की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी का पूर्णतः उत्तरदायित्व



होगा। जो बिल कोषागार को भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाय, उनमें स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ सम्बन्धित अनुदान संख्या/मद का भी उल्लेख अवश्यमेव किया जाय, स्वीकृत धनराशि का व्ययवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।

- (vii) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रक्रियानुसार कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित बजट की सीमा तक प्रपत्र बी0एम0-08 पर व्यय विवरण शासन के प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को माह की अगली 05 तारीक तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाएगा।
- (viii) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय, उक्त मद में व्यय करने के उपरांत यदि धनराशि अवशेष रह जाती है तो प्रशासकीय विभाग को इसकी सूचना अनिवार्य रूप से दी जाय ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- (ix) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि (वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के पैरा-162) समस्त आहरित अग्रिमों का समायोजन आहरण-वितरण अधिकारियों द्वारा 30 दिनों के अन्दर कर दिया जाय तथा डीटेल्ड कन्टीजेन्ट (डी0सी0) बिल महालेखाकार को भेज दिए जाय। विभिन्न अग्रिमों का आहरण अधिकारों के प्रतिनिधायन 2010 में दी गई सीमाओं के अनुसार ही किया जाय।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या:145(P)/XXVII(3)/2013-14 दिनांक: 30 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति तथा वित्त विभाग के शासनादेश संख्या: 284/XXVII(1)/2013 दिनांक: 30.3.2013 में निहित प्राविधानुसार एवं [www.cts.uk.gov.in](http://www.cts.uk.gov.in) से साफ्टवेयर के माध्यम से निर्गत विशिष्ट एलॉटमेंट आई0डी0संख्या-H1462110650 (प्रति संलग्न) द्वारा निर्गत किए जा रहे हैं।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 हेतु लेखानुदान के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा-03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा-102-विश्वविद्यालयों को सहायता-आयोजनागत-08-श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता की सुसंगत इकाई के नामें डाला जायेगा।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीया,

(मनीषा पंवार)  
सचिव

पृष्ठांकन संख्या:65 /XXIV(6)/2014/33(4)12 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
3. कोषाधिकारी, टिहरी।
4. जिलाधिकारी, टिहरी।
5. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, (DSIO), टिहरी गढ़वाल।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, उत्तराखण्ड।
8. वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन।
9. बजट राजकोषीय, नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)

उप सचिव।